

संपादकीय

सूखे की गिरफ्त में

मॉनसून में देरी ने देश में सूखे के संकट को गंभीर बना दिया है। आईआईटी, गांधीनगर द्वारा चलाए जा रहे सूखा प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के अनुसार देश के 40 फीसदी से अधिक क्षेत्रों में सूखे का संकट है जबकि ड्राइट अर्ली वार्निंग सिस्टम (इयूज) के अनुसार देश के 44 फीसदी हिस्से किसी न किसी रूप में सूखे से प्रभावित हैं। चालू मॉनसून सीजन में मॉनसून का आगमन ही 8 दिन की देरी से हुआ है। साथ ही कई राज्यों में प्री-मॉनसून की बारिश भी सामान्य से काफी कम हुई है जिसकी वजह से भयावह जल संकट पैदा हो गया है और कृषि पैदावार में भी कमी आने की आशंका गहरा रही है। 20 जून को समाप्त सप्ताह के दौरान देश के 91 प्रमुख जलाशयों में 27.265 फीसदी (बिलियन क्यूबिक मीटर) जल संग्रह हुआ। यह इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का मात्र 17 प्रतिशत है। पिछले दिनों चेन्नै के संकट की खबर आई। वहां इसी सप्ताह चार जलाशय सूख गए और अब बहुत कम मात्रा में पानी बचा हुआ है। संकट दूर करने के लिए वहां वेलोट के जोलारपेट से एक करोड़ लीटर पानी विशेष ट्रेन के जरिए भेजा जाएगा।

दूसरे महानगरों का भी हाल बहुत अच्छा नहीं है। बंगलुरु का भूजल स्तर पिछले दो दशक में 10-12 मीटर से ऊपर कर 76-91 मीटर तक जा पहुंचा है। दिल्ली का भूजल भी लगातार कम हो रहा है। महाराष्ट्र 47 साल का सबसे बड़ा सूखा झेल रहा है। अन्य कई राज्य भी इसकी चपेट में आ गए हैं। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार अगले एक वर्ष में जलसंकट की इस समस्या से 10 करोड़ लोग प्रभावित होंगे, वहीं 2030 तक देश की 40 फीसदी आबादी इस गंभीर समस्या की चपेट में होगी। सच तो यह है कि मौसम में आ रहा बदलाव लगातार हमारे ऊपर गहरा असर डाल रहा है। इस बदलाव को अच्छे से समझकर उसके अनुरूप नीतियां बनानी होंगी। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के मुताबिक 2018 में बारिश में 9.4 फीसदी की कमी आई थी। बारिश में लगातार कमी का यह पांचवां साल था। जाहिर है, बारिश में लगातार कमी आती जा रही है। इसे नोटिस में लेने की जरूरत है। हम यह मानकर नहीं बैठ सकते कि हालात

कभी बदल भी सकते हैं। जिस तरह सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया है, उसी तरह मॉनसून के आकलन और उसके मूलाधार रणनीति तैयार करने के लिए एक विशेष तंत्र की जरूरत है। अभी तमाम फौरी राहत उपाय करने चाहिए, लेकिन कई दीर्घकालीन कदम भी उठाने होंगे। जल प्रबंधन के साथ सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता देनी होगी, सूखा प्रतिरोधी फसलों को बढ़ावा देने के साथ पौधारोपण जैसे कार्यक्रमों को बढ़ावा देना होगा।

टिक्का मसाला बनाने विधि ...

सामग्री:



को अच्छे तरीके से मिक्स करें। 5.

अब एक पैन में 50 ग्राम मटखने लें,

जिसमें 140 ग्राम व्याज अच्छी तरह

ब्राउन होने तक भूमि। 6. उस सामग्री

में 70 ग्राम पारता तोंस को अच्छी

तरह से मिक्स करें। 7. फिर 1 टेबलस्पून

फ्रेंश क्रीम और 1 टीस्पून नमक डालकर

अच्छी तरह से मिक्स करें। 8. अब सारी

सामग्री को 7 से 8 मिनट तक धीमी आंच

पर पकाएं। 9. गर्म होने के बाद एक लैंडर

में डाल दें। लैंडर में तैयार दही और

पेस्ट को मैसे करें। 10. अब एक मिलिसेंग

बातल में उबल हुआ पास्ता, तैयार तोंस, 80

ग्राम देढ़ चीज़, 80 ग्राम मोजरेला चीज़

डालकर अच्छी तरह मिलाएं। 11. तैयार

सामान को बैंकिंग ट्रे में निकाल लें, अब

देढ़ चीज़ और मोजरेला चीज़ के साथ

गर्मियों को 12. तैयार सामग्री को आगे में

180 डिग्री पर तैयार होने तक पकाएं। 13.

अब इसे ओवन से निकालें और बारिश करे

धनिया के साथ गर्निश करें। 14. टिक्का

मसाला में एक चीज़ बनाकर तैयार है, इसे

गर्म-गर्म सर्व करें।

आरबीआई अधिशेष पर जालान समिति में मतभेद बरकरार, रिपोर्ट लंबित



नईदिल्ली (आरएनएस)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अधिशेष का सरकार को हस्तांतरण किए जाने पर कैसला लेने वाली समिति की रिपोर्ट सौंपने में फिर विलंब हो गया है। सूत्रों ने बताया कि आरबीआई की इकानोमिक फेमर्क लैपिटल (ईसीएफ) समिति के सदस्यों में केंट्री बैंक की अधिशेष निधि के वितरण को लेकर मतभेद बरकरार है, इसलिए बिमल जालान की समिति की वैठक होगी, जिसमें आगुवाई वाली है।

अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए और समय मांगा है। पूर्व बाबू आई डिल्ली गवर्नर राकेश मोहन उपाध्यक्ष हैं और उनके अलावा समिति में गर्ग, आरबीआई केंट्री बैंक के सदस्य भरत देवी और सुधीर मांकड़ और आरबीआई के डिल्ली गवर्नर एस. विश्वानाथन शामिल हैं। सूत्रों ने बताया कि समिति के कारण चौथी बार लंबित होने के कारण चौथी बार लंबित हो गई। सूत्रों के अनुसार, आरबीआई की अत्यधिक निधि को चरणबद्ध तरीके से कम करने के पक्ष में है, लेकिन सरकार को निधि के हस्तांतरण के पक्ष में नहीं है।

अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए और समय मांगा है।

पूर्ण बजट के संसद में पेश होने के बाद फिर जुलाई में आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जालान की अध्यक्षता में ईसीएफ समिति की वैठक में शामिल नहीं हो पाए।

छह सदस्यीय इस समिति में

पूर्व आरबीआई डिल्ली गवर्नर राकेश मोहन उपाध्यक्ष हैं और उनके अलावा समिति में गर्ग, आरबीआई केंट्री बैंक के सदस्य भरत देवी और सुधीर मांकड़ और आरबीआई के डिल्ली गवर्नर एस. विश्वानाथन शामिल हैं। सूत्रों ने बताया कि समिति के कुछ सदस्य आरबीआई की अत्यधिक निधि को चरणबद्ध तरीके से कम करने के पक्ष में है, लेकिन सरकार को निधि के हस्तांतरण के पक्ष में नहीं है।

हवाई यातायात नियंत्रकों को 31

दिसंबर तक लेना होगा लाइसेंस

नईदिल्ली (आरएनएस)।

हवाई यातायात नियंत्रक (एटीसी)

अधिकारियों के

लिए पहली बार लाइसेंस की

व्यवस्था करने के बारे सरकार

ने सभी मौजूदा एटीसी

अधिकारियों के

लिए लाइसेंस

हासिल करने के लिए 31

दिसंबर 2019 तक का समय

तय किया है।

नागरिक उड़ान क्षेत्र की

अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के दबाव में

भारत ने करीब छह महीने पहले

विदेशों की तर्ज पर भारतीय

एटीसी नियंत्रकों के

लिए भारतीय नियंत्रकों

की जिम्मेदारी दी जाती है।

नागरिक उड़ान क्षेत्र की

अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के दबाव में

भारत ने करीब छह महीने पहले

विदेशों की तर्ज पर भारतीय

एटीसी नियंत्रकों के

लिए भारतीय नियंत्रकों

की जिम्मेदारी दी जाती है।

नागरिक उड़ान क्षेत्र की

अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के दबाव में

भारत ने करीब छह महीने पहले

विदेशों की तर्ज पर भारतीय

एटीसी नियंत्रकों के

लिए भारतीय नियंत्रकों

की जिम्मेदारी दी जाती है।

नागरिक उड़ान क्षेत्र की

अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के दबाव में

भारत ने करीब छह महीने पहले